Intent issued for setting up new sugar units and for expansion of capacity:

Year	New Units	Substantial Expansion	Total
1994	66	29	95
1995	2	—	2
1996 (Upto Feb, 96)	—	4	4
Total	68	33	101

(b) to (e) The target for creation of capacity in the sugar sector during the Eighth plan period was 25.15 lakh tonnes of sugar. Plan targets for creation of capacity in any sector are indicative in nature and they by themselves do not suggest any capacity constraint in the sector. Receipt and processing of applications for Industrial Licences is an ongoing process. The Letters of Intent in any sector including the sugar sector is initially valid for 3 years which is extendable on merits of individual cases, during which during which time the letter of intent is required to be converted into Industrial Licence on fulfilment of conditions of Letter of Intent. The licence holder is required to commence commercial production within 2 years of obtaining the Industrial Licence.

उत्तर प्रदेश की लोक सेवा आयोग — 1992 की परीक्षा के परिणाम में अनियमितताएं

758. **मौलाना औबैदुल्ला खान आज़मी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा घोषित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (मुख्य) परीक्षा, 1992 के परिणामों के अनुसार 85% परीक्षार्थी केवल एक वैकल्पिक विषय अर्थात् संस्कृत से सफल हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या एक ही वैकल्पिक विषय के परीक्षार्थियों का सफल होना परीक्षाफल की संदिग्धता को दर्शाता है;

(ग) क्या इसमें बरती गई अनियमितताओं के कारण आयोग के तीन सदस्यों ने परीक्षाफल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो अनियमिताओं को समाप्त करने और परीक्षाफल को निष्पक्ष बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) और (ख) जी नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार इस परीक्षा के लिखित इम्तहान के हाल ही में घोषित किए गए परिणामों में उम्मीदवारों की सफलता किसी एक वैकल्पिक विषय में प्राप्त अंकों पर आधारित नहीं थी।

(ग) जी नहीं। परिणाम की घोषणा आयोग के सभी सदस्यों के अनुमोदन से की गई थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Privatisation of Irrigation Projects

759. SHRI PRAMOD MAHAJAN :
SHRI VIREN J. SHAH :
SHRI SANJAY DALMIA :
SHRI ISH DUTT YADAV :
SHRI K.M. KHAN :

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether the committee set up by Government to examine the feasibility, extent and modalities of privatisation in the light of inadequate funding and delays in completion of on-going irrigation projects, has submitted its report;

(b) if so, the details of the recommendations made by the Committee in respect of each project; and

(c) the present position of each of the on-going irrigation projects in Maharashtra and Gujarat which have been delayed on account of resource crunch and also the details of the projects which are proposed to be handed over to the private sector?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATE RESOURCES (SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU) : (a) Yes, Sir.

(b) The Committee has not made any recommendations in respect of each Project. However, it has concluded that

while Private Sector's participation is feasible in respect of all irrigation (Surface and Grond Water) and Multi-Purpose Projects, it would be desirable to introduce this on a pilot basis for select Projects that do not have problems of inter-state issues/security, etc. The Committee has also recommended on various other related aspects like basis of Private Sector participation, financial aspects, legal aspects, concessions to be offered to Private investors, etc.

(c) Statement is enclosed.

Statement

Maharashtra

32 major and 53 medium irrigation Projects of Maharashtra spilled over to VIII Plan. The region-wise irrigation projects identified by the Government of Maharashtra for posing to private Sector are as under:

	Region	Number of Projects	Major Irrigation Projects	Madium Irrigation Projects	Minor Irrigation Schemes	Lift Irrigation Schemes	Estt.Cost Rs.lakhs
1.	Konkan	4	0	1	3	—	15,703
2.	Pune	7	1	4	2	—	19,721
3.	Nashik	14	0	5	9	—	21,139
4.	Aurangabad	8	0	2	6	—	8,158
5.	Nagpur	12	0	5	4	3	21,826
6.	Amarvati	7	0	2	5	—	7,489
	Total	52	1	19	29	Total	94,036

Gujarat

9 major and 25 medium irrigation projects of Gujarat spilled ober to VIII Plan. Govt. of Gujarat is presently contemplating farmers' participation and turn over to water usar associations in respect of medium and minor irrigation schemes. For major irrigation projects, studies have been initiated for joint venture.

आइस क्रीम को आरक्षित सूची से बाहर निकालने के संबंध में प्रस्ताव

760. **श्रीमती सुषमा स्वराज:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आइस क्रीम को लघु उद्योगों के लिए आरक्षित उत्पादों की सूची से बाहर निकालने का निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार लघु उद्योगों के लिए आरक्षित उत्पादों की सूची से अन्य वस्तुओं को भी बाहर निकालने का विचार रखती है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि सरकार को आरक्षित सूची से कुछ और उत्पादों को बाहर निकालने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए है; और

(ङ) यदि हां, तो उत्पादों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार ने लघु उद्योगों के लिए आरक्षित उत्पादों की सूची में से आईस-क्रीम को हटाने संबंधी कोई निर्णय नहीं लिया है। आईस-क्रीम लघु उद्योग क्षेत्र के लिए ही आरक्षित रहेगी।

(ग) से (ङ) सरकार ने आई० डी० आर० अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत आरक्षण संबंधी सलाहाकार समिति का गठन किया है जो आरक्षित/अनारक्षित मदों पर विचार करती है और समय-समय पर सरकार को सिफारिश करती है। सरकार व्यक्तियों/संस्थाओं/मझौले/बड़े उपक्रमों इत्यादि से नई मदों और मदों के अनारक्षण/नामप्रणाली में परिवर्तन